प्रेषक,

राजीव रौतेला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 13 अगस्त, 2014**

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत एस0एल0ई0सी0 सब कमेटी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-247/खा0प्र0मि0/86/13-14/ लखनऊ, दिनांक- 10/06/2014 एवं अन्य का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-431/58-2-2013-17/13, दिनांक- 08.08.2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 20.01.2014 द्वारा निम्न संस्थाओं को अनुदान की संस्तुति प्रदान की गयी है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	**सूची क्रमांक**	**संस्था का नाम**	**अनुदान की धनराशि**	**प्रथम किस्त**
1	1	मै0 श्री मनमोहन फूड प्रा0लि0, सी0-5 इण्डस्ट्रीयल एरिया, अमावन रोड, रायबरेली के ब्रेड/बेकरी इकाई की स्थापना	50.00	25.00
2	2	मै0 श्याम राईस इण्डस्ट्रीज, बी0-6, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, महराजगंज, रायबरेली, के राईस मिल के आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण हेतु	21.38	10.69
3	5	मै0 सिंघानिया एग्रो इण्डस्ट्री प्रा0लि0, ग्राम- रामनगर, हरदोई रोड, सीतापुर का तिल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु	50.00	25.00
4	6	मै0 अम्बिका राईस मिल, इटावा रोड, मैनपुरी के राईस मिल के विस्तारीकरण हेतु	21.41	10.705

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

5	7	मै0 नारायण उद्योग ग्राम-दखिनारा, एटा रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद के राईस मिल के आधुनिकीकरण हेतु	35.21	17.605
6	9	मै0 श्री तिरूपति बालाजी इण्डस्ट्रीज, प्रा0लि0 प्लाट नं0-डी-34,35,72,73 यू0एस0आई0डी0सी0 एग्रो पार्क, खरखियान फूलपूर, वाराणसी के बेकरी इकाई की स्थापना हेतु	48.61	24.305
		;kx	**226.61**	**113.305**

3. उक्त संस्तुति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 आयोजनागत पक्ष में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन हेतु शासनादेश संख्या-32/477/58-2-2014-300(14)/2014, दिनांक-10.06.2014 द्वारा रू0-2,61,88 हजार (रूपया दो करोड़ इकसठ लाख अठठासी हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या-37/671/58-2-2014-300(14)/2014, दिनांक-06/08/2014 द्वारा रू0-14,73,04 हजार (रूपया चौदह करोड तिहत्तर लाख चार हजार मात्र) आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. उपलब्ध धनराशि में से तालिका में अंकित संस्थाओं को उनके सम्मुख अंकित अनुदान की प्रथम किस्त कुल धनराशि रू0-**113.305** लाख (रूपया एक करोड तेरह लाख तीस हजार पाँच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन द्वारा कराया जायेगा।

(2) अनुदान हेतु स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि जारी करने से पूर्व भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा किया जायेगा तथा उसकी मासिक आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक- 31.03.2015 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु आप स्वयं तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(8) भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(9) उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(10) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-।।, दिनांक: 29 मई, 2012 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(11) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22/07/2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव रौतेला)
विशेष सचिव।

संख्या-40/514(1)/58-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।

(2) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(3) संबंधित जनपदों के आयुक्त/जिलाधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

(4) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(8) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in